(c) to what extent this package envisages private sector participation in making these ailing units productive and contribute much needed fertilizer to the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO); (a) to (c) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has declared two fertilizer producing public sector undertakings, namely, Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCI) and Hindustan Fertilizer Corporation of India Ltd (HFC) as sick companies under the provisions of the sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. The BIFR has appointed Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) as the Operation Agency to prepare revival/rehabilitation packages in respect of these companies. Any decision on the revival of these companies, including the role of private sector in their revival, would depend upon the outcome of the proceedings pending before the BIFR, which is a quasi-judicial authority.

Government have not finalised any new package for revamping the sick fertiliser units in the public sector. A Technical Committee was set up in June, 1994 merely to assess the minimum requirement of funds for replacement of trouble prone equipment etc. in respect of a few units of HFC, and to assess the levels of production likely to be achieved after the above investments and to workout financial viability of these investments under alternative scenario*.

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं

319. **श्री अजीत जोगी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कतिपय पुनर्वास परियोजनाओं का परित्याग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी वैकल्पिक पुनर्वास योजनायें शुरू की गई हैं/शुरू करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फलैरियो) : (क) से (घ) भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना को मध्य प्रदेश सरकार कार्यान्वित कर रही है ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस कार्य योजना के अधीन कुछ स्कीमें अर्थात् स्वास्थ्य शिक्षा, प्रोटीन की कमी दूर करने की स्कीम घरों और बस्तियों, सेवा केन्द्रों का पुनर्निर्माण, स्टेप-अप सब्सिडी तथा स्टाफ वृत्तिका या तो इसी तरह की स्कीमों से परस्परव्यापी (ओवर-लैपिंग) थी या यह पाया गया था कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है । अतः इन्हें समाप्त कर दिया गया था और इस तरह से बचे धन को अन्य स्कीमों को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया था ।

कोरबा उर्वरक संयंत्र

320. **श्री अजीत जोगी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उर्वरक संयंत्र की लाखों रुपयों की मशीनरी कोरबा में निष्क्रिय पड़ी है क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम प्रस्तावित उर्वरक एकक को स्थापित करने में असफल रहा है ;

(ख) इस मशीनरी तथा अन्य निर्माण सामग्रियों को उपयोग में लाने की सरकार की क्या योजना है ;